Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 19-12-2006

Participants : Yadav Shri Ram Kripal

>

Title: Need to enact a law to regulate the credit card services provided by various private banks. .

श्री राम कृपाल यादव: एक मिनट तो कहते हुए ही खत्म हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अत्यन्त ही गम्भीर सवाल की तरफ आकर्ति करना चाहता हूं। देश की ज्यादातर गैरसरकारी बैंकिंग कम्पनियां भोले-भाले उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड का लाभ बताकर, उनको बहला-फुसलाकर क्रेडिट कार्ड बना देते हैं। ये बैंक अपने उपभोक्ताओं को ज्यादातर शर्तें नहीं बताते हैं, जिससे उपभोक्ता इनके जाल में फंस जाते हैं और बैंक इनसे मनमाना सूद वसूलते हैं। यह सूद लगभग 40 प्रतिशत सालाना होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये बैंक अपने कार्ड को किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं किये जाने के बावजूद उनके कार्ड असेसमेंट के खर्च दिखाते हैं और उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलते हैं। इन बैंकों में ICICI बैंक, सिटी बैंक, HDFC बैंक काफी अलोकप्रिय हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इनकी निगरानी करें तथा भोले-भाले उपभोक्ताओं को, जो बड़े पैमाने पर चीट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ऐसा सख्त कानून बनायें, ताकि जो बेचारे भोले-भाले उपभोक्ता हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो सके, उनके साथ चीटिंग नहीं हो सके। इस पर अविलम्ब कोई ठोस कानूनी कार्रवाई करायें, कानून बनायें, ताकि इन सब चीजों पर नियंत्रण हो सके और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक, जो आम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, खासकर जो प्राइवेट बैंक हैं, उन पर अंकुश लगायें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी बोलिए। हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वन बाई वन आ रहा हूं।